[श्री देवराव पाटिल]

जो यह आम तौर पर कहा जाता था कि सच्चा टप्पाखाना, चोट्टी करोडगीरी और माल में पालमपोल तो डाकखाने के बारे में वह जो कहा जाता था सच्चा टप्पाखाना वह बात अब सोलहों आने ठीक उत्तर रही है और डाकखानों के बारे में हमारे पास शिकायतें आती रहती हैं और उस का एक उदाहरण मैंने वह 250 रुपये के मनीआर्डर की नौन डिलीवरी का दिया। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान दें और डाकखानों के स्टाफ के बारे में जो शिकायतें हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे ताकि यह धब्बा इस डिपार्टमेंट के नाम पर से हट जाय।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण की व्यवस्था की ओर मैं डा० राम सुभग सिंह का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस में उन्हें बुनियादी परिवर्तन करना चाहिये। अब अगर देहाती इलाकों में आप यह डाकघर रेम्युनरेटिव बेसिस पर कायम करना चाहते हैं तो वह एक गलत चीज हैं। जाहिर है कि देहात में कम लोग रहते हैं, देहातों की नेशनल इनकम कम है जब कि शहरी इनकम ज्यादा है। देहातों में लोग गरीब हैं और अगर आप ऐसे गांवों में पैसा देने पर डाकखाना देने की योजना शुरू करेंगे तो कोई ऐसा वक्त कभी नहीं आयेगा कि हर एक गांव में आप डाकघर दे सकेंगे। यह एक गलत चीज है कि सब विकास की योजना आप शहरी लोगों के लिए करते हैं देहात के लोगों के लिए आप करना नहीं चाहते हैं। कोई भी छोटा देहात आप को ऐसा नहीं मिलेगा जो कि पोस्ट आफिस के लिये रकम दे सकता है। मेरा सुझाव यह है कि अब आप गांव में डाकघर यानी विलेज ए पोस्ट स्कीमें शुरू करें और इसके लिए बाकायदा एक योजना बना कर और फेज प्रोग्राम देकर आप को कार्य आरम्भ कर देना चाहिऐ ताकि 5-10 साल के अन्दर हर एक गांव में पोस्ट आफिस बन जाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि मन्त्री महोदय इस पर ख्याल करेंगे और हर एक देहात में पोस्ट आफिस देने की व्यवस्था करेंगे। यह एक बहुत जरूरी चीज हैं।

कहना तो मुझे अभी बहुत कुछ था लेकिन चूंकि कई मर्तबा घंटी बज चुकी है इस लिये मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

18.15 hrs

STATEMENT *RE* : ARRESTS OF M. PS. IN KUTCH AREA

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : According to information received from the Gujarat Government, the District Magistrate, Kutch, issued an order on April 20 under Section 144 Cr. P. C. prohibiting entry into the Rann of Kutch. The order specified that satyagrahis would not be permitted to proceed beyond a particular point from where they planned to enter the prohibited area. On April 21, when satyagrahis reached that point, the police officers drew their attention to the prohibitory order but the satyagrahis proceeded into the prohibited area. They were accordingly given directions to leave the area under section 68 of the Bombay Police Act which lays down that all persons shall be bound to conform to the reasonable directions of a police officer given in fulfilment of any of his duties under that Act which include prevention of commission of even non-cognizable offences within his view. As the satyagrahis did not leave the prohibited area, they were *restrained* and removed by the police under section 69 of the Bombay Police Act. The five M. Ps. and other leaders were taken by State Transport buses to Gandhidham which is the nearest railway station about 28 miles from Khavda.

Some Hon. Members *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is not the practice... *(Interruption)*

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : Some questions should be allowed to be put.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You wanted to know the facts. This morning you raised this issue and he, naturally, thought that he should make a statement giving the general facts of the case. Normally, the practice followed is that no questions are permitted.....*(Interruption)*

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara): It is not the question.....*(Interruption)*

श्री रवि राय (पुरी) : बिना वारंट के इस तरह से संसद् सदस्यों को पकड़ना कितनी गलत चीज है ? इस तरह से एम पीज पर पुलिस का जुल्म चलता रहेगा और आप यहां पर उस बारे में बोलने भी नहीं देना चाहते । हमें गृह मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्टीकरण तो मांग लेने दीजिये । इस तरह से बिना वारंट के 5 संसद सदस्य गिरफ्तार हो जायं यह एक साधारण घटना नहीं है और इसलिए इसे एक असाधारण घटना मान कर इस पर हमें स्पष्टीकरण मांगने दीजिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : If I permit one, I will have to permit others..... *(Interruption)*. On the basis of this statement, there are other ways to put questions at a later stage, not now.

———

18.19 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69—*Contd.*

Department of Communications—*Contd.*

श्री ना० नि० पटेल (बलसार) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर जनरल पब्लिक का सम्बन्ध सरकार के किसी डिपार्टमेंट से सब से ज्यादा है तो वह यह डाक व तार विभाग का मुहकमा है । डाक, तार मुहकमे के अधीन काम करने वाले कर्मचारी लोग और सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तुलना में अधिक मेहनत व ईमानदारी से अपना कर्त्तव्य निबाहते हैं । अब इसके विपरीत रेलवे के बुकिंग क्लर्क को आप ले लीजिये वह टिकट के लिए जाने वाले ग्रामीण मुसाफिरों से और जोकि जल्दी में होते हैं क्योंकि ट्रेन पकड़नी होती है उन से वह ज्यादा पैसे ले लिया करते हैं । इस तरह से ऊपर से वह पैसे उस जगह पर बैठकर बनाता है । इसी तरह से पार्सल क्लर्क भी पार्सल छुड़ाने वालों से 2, 4 रुपये ऊपर ले ही लेता है । इसी तरह से पुलिस के सिपाही को भी ऊपर से पैसे मिल ही जाया करते हैं । साइकिल में बत्ती नहीं है या डबल राइडिंग साइकिल पर हो रही है तो वह सिपाही पुलिस का 2, 4 रुपये उन आदमियों से बना लेता है । लेकिन जहां तक इस पोस्टल डिपार्टमेंट का सवाल है उनको वह डाक टिकट, लिफाफे व पोस्टकार्ड गिन कर दिये जाते हैं और आने आने और पाई, पाई तक का हिसाब हो जाता है । वह एक पैसे का भी इधर, उधर नहीं कर सकता है । जहां तक उनके द्वारा ड्यूटी देने का सम्बन्ध है यह बेचारे पोस्टमैन बारिश के दिनों में और तपती गरमी व लू के मौसम में चिट्ठियां बांटते पैदल घूमते हैं और गरमी में जब पसीना बहता है तो उसके बदन पर नमक पड़ता है । वैसी उनकी हालत है । देने के वक्त सब चिल्लाते हैं कि उनके रहने के लिये कुछ नहीं है, दूसरी कोई सुविधा नहीं है । सुविधा सब चाहते हैं कि दी जाय, लेकिन पैसा कहां से लायें ? बिना पैसे के कैसे काम चल सकता है ? अगर आप बढ़ाना चाहते हैं । तो बढ़ाइये, ठीक है क्योंकि बिना बढ़ाये कैसे काम चल सकता है, लेकिन इसका इन्तजाम तो होना चाहिये । पोस्टकार्ड पर पैसा बढ़ गया तो कहते हैं कि दिक्कत है और नहीं बढ़ना चाहिये । लेकिन दूसरी तरफ आप देखिये कि पहले खाने का पान दो पैसे में मिलता था, लेकिन उस दिन मैंने पार्लियामेंट में लिया तो 15 पैसे का मिला और वह भी सिंगल पान, जिसमें सिर्फ कत्था सुपारी था, तम्बाकू नहीं थी । इसको कोई नहीं सोचता । उस को लोग खा कर थूक देते है और दीवार गंदी करते हैं । तो यह तो ठीक हैं कि सुविधा देनी चाहिये, लेकिन उसके लिये पैसा तो हो । पैसा कहां से लायेंगे ? ठीक है, जरूरत है, और इस पर सीच विचार करना चाहिये ।